

दुनिया के शक्ति संतुलन में पूँजीवाद और साम्यवाद के बीच लम्बी प्रतिस्पर्धा चली। पूँजीवाद का नेतृत्व अमेरिका के पास था और साम्यवाद का रूस के पास। अमेरिका व्यावसायिक बुद्धि के आधार पर दुनिया भर के देशों का शोषण करता था और अपने देश के नागरिकों को सुख सुविधा सम्पन्न बनाये रखता था जबकि रूस सैनिक बुद्धि के अन्तर्गत अपने देश के लोगों का पेट काट काटकर भी दूसरे देशों की सहायता में लगा रहता था। अमेरिका ने धन के बल पर बुद्धि खरीदी किन्तु रूस इस मामले में पूरी प्रतिस्पर्धा करने के बाद भी पिछड़ा रहा। ऐसे ही समय में एक ऐतिहासिक घटना क्रम के अन्तर्गत रूस के राष्ट्रपति पद पर गोर्बाचोव बैठे। उन्होंने सम्पूर्ण स्थिति की विस्तृत सीमक्षा की और पाया कि अमेरिका के साथ सैनिक प्रतिस्पर्धा न ही किसी प्रकार भी न्यायसंगत है न ही तर्क पूर्ण। सैनिक शक्ति के बल पर बनी लौह दीवारें लम्बे समय तक एकता बनाकर नहीं रख सकतीं न ही ऐसा बनाये रखना किसी भी रूप में मानवीय ही है। उन्होंने सैनिक शक्ति के बल पर बनी लौह दीवारों को तुड़वा दिया और दीवारों के टूटते ही उसके अन्दर के साम्यवादी देश एक एक करके दीवार से बाहर कूद गये। रूस और चीन ने भी सैनिक प्रतिस्पर्धा के स्थान पर व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का मार्ग पकड़ा। आज यह सिद्ध हो चुका है कि गोर्बाचोव के इस परिवर्तन के कारण ही अमेरिका पूरी दुनियाँ का एकछत्र मार्ग दर्शक बनने में सफल हुआ किन्तु रूस और चीन के आम नागरिक आज पहले की अपेक्षा बहुत अधिक स्वतंत्र और सुख सम्पन्नता का अनुभव करते हैं। गोर्बाचोव का यह परिवर्तन साम्यवादी इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में भले ही लिखा जायगा किन्तु सम्पूर्ण विश्व के मानवीय इतिहास में उनका नाम स्वर्णाच्छरों से अंकित होगा।

दुनिया भर के साम्यवादी देशों ने साम्यवाद की विफलता स्वीकार कर ली किन्तु दुनिया भर के साम्यवादियों ने पूरी तरह हार नहीं मानी। वे प्रजातांत्रिक तरीके से अभियान चलाते रहे। उन्होंने मुसलमानों की बन्दूक मुसलमानों के ही कन्धों पर रखकर अमेरिका के विरुद्ध चलानी शुरू कर दी और एक ऐसा समीकरण बनाया कि अमेरिका के विरुद्ध वातावरण बनाने में साम्यवादियों को काफी सफलता मिली भले ही मुसलमानों का चाहे जो भी नुकसान हुआ हो। साम्यवाद के पास तो खोने को कुछ था भी नहीं इसिलिये अमेरिका के विरुद्ध आग उगलने से उन्हें कोई नुकसान न हो सकता था न हुआ।

भारत के साम्यवादी अपनी इस कूटनीति में बढ़ चढ़ कर आगे रहे। किन्तु उन्हें यह अच्छी तरह पता था कि अमेरिका विरोध के नाम पर भारत में राजनैतिक छलांग लगाना संभव नहीं हैं। अतः साम्यवादियों ने कांग्रेस की बन्दूक श्रमजीवियों के कन्धों पर रखकर ऐसा कूटनीतिक आक्रमण किया कि अटल बिहारी वाजपेयी की मजबूत किलेबंदी भी ध्वस्त हो गई। एकाएक अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस सत्ता में आई और साम्यवादियों को अमर बेल के समान कांग्रेस के उपर छा जाने का अवसर मिल ही गया। कांग्रेस न शुरू से ही महसूस किया कि वामपंथी अर्थनीति जन आक्रोश में तो पूरी तरह उपयोगी हो सकती है किन्तु इससे न देश को समृद्ध बनाया जा सकता है न समाज को। देश और समाज को समृद्ध बनाये रखने के लिये तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा को खुला प्रोत्साहन देना ही होगा। यह बात सब जानते भी हैं और मानते भी हैं कि साम्यवादी अर्थनीति में राष्ट्र भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़ता है और समाज भी किन्तु आर्थिक विषमता बहुत तेजी से बढ़ती है अर्थात् पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में साम्यवादी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अमीर हवाई जहाज की गति से आगे बढ़ता है और गरीब चींटी की चाल से। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने अपनी पूँजीवादी

अर्थव्यवस्था को इस प्रकार जारी रखा कि थोड़ी कम रफ्तार से वे चलते भी रहें और साम्यवादी विरोध कम करके उसका लाभ भी उठाते रहे। सेज की योजना एक ऐसा ही कदम था जो भारत की आर्थिक स्थिति में तेज छलांग लगा सकती हैं इतनी तेज की दुनिया की अन्य पूँजीवादी देश भी परेशान हो जावें। इस योजना से गरीब से गरीब का भी जीवन स्तर सुधरेगा यह बिल्कुल निश्चित है किन्तु इस योजना के लाभ का अधिकांश हिस्सा तो हाथियों को ही जायेगा, चीटियाँ तो सिर्फ दाने तक ही रह जायेगी।

बुद्धदेव जी की स्थिति अन्य साम्यवादियों से भिन्न थी। बंगाल कोई पृथक देश नहीं था कि उसे लौह कवच में रखा जा सके। राजनैतिक रूप से तो बंगाल को लौह दीवार सरीखा सुरक्षित कर दिया गया किन्तु आर्थिक रूप से तो हवा में लाठी नहीं चल सकती। यदि भारत के अन्य प्रदेश उद्योग लगा लगाकर अपने अपने क्षेत्रों का आर्थिक विकास तेजी से कर लें तो बंगाल टापू के समान कब तक सुरक्षित रह सकेगा। परिणाम स्वरूप बुद्धदेव जी ने परिस्थितियों का ठीक से आकलन करके यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया ठीक समझा और गोर्बाचोव की राह पकड़ी जो न्याय संगत भी है और तर्क संगत भी किन्तु साम्यवाद की संभावनाओं को भारत में सदा सदा के लिये समाप्त कर सकती हैं। साम्यवादी रणनीति का पहला पाठ ही यह है कि समस्याओं का समाधान वर्ग संघर्ष में बाधक है। बुद्धदेव जी की मजबूरी थी कि वे समस्याओं के समाधान में अलग थलग न पड़ जावें।

भारत के मार्क्सवादियों ने तो किसी तरह छाती पर पत्थर रखकर बुद्धदेव जी का समर्थन कर दिया और रही सही कसर चीन के राष्ट्रपति ने अपनी भारत यात्रा में पूरी कर दी किन्तु भारत के अन्य वामपंथी अपनी मौत खुद बुलाने को तैयार नहीं हुए। वे भीतर ही भीतर कसमस रहे थे कि चालाक ममता बनर्जी मौके का फायदा उठाकर मैदान के अकेले और बिना योजना के कूद पड़ी। मेधा पाटकर जैसे प्रच्छन्न वामपंथियों ने भी तत्काल ममता का साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी को भी ममता के समर्थन में लाभ दिखा भले ही उसकी कितनी भी जग हंसाई क्यों न हुई हो। राजनीति का ऐसा चरित्र पतन शायद दुनियाँ में देखने को न मिले कि अपने अपने राज्यों में सेज लागू करने के लिये आगे आगे दौड़ लगाने वाली भाजपा भी बंगाल में सेज के विरुद्ध मोर्चे पर आ गई। नक्सलवादियों ने तो खुलकर ही मोर्चा सम्हाला। धीरे धीरे अन्य वामपंथी भी प्रश्न खड़े करने लगे। एक माह पहले ही बुद्धदेव जी की भरपूर प्रशंसा करने वाले मनमोहन जी ने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। मार्क्सवादी कार्यकर्ता भी बुद्धदेव जी का समर्थन करने में हिचकिचाने लगा। बुद्धदेव जी स्वयं को अकेला महसूस करने लगे और धीरे धीरे बढ़ते कदम रोकने में ही भलाई समझी। आज बुद्धदेव जी की हालत यह हो गई है कि नन्दीग्राम संघर्ष में मरने वाले अधिकांश लोग मार्क्सवादी भी हो सकते हैं क्योंकि अब तक यह प्रमाणित नहीं हुआ कि किस गुट के लोग मरे लेकिन सारी दुनियाँ में यह प्रचारित हो गया है कि मार्क्सवादीयो ने दूसरे गुट की हत्याएँ की हैं और जीवन भर असत्य को सत्य प्रमाणित करने में सिद्धहस्त मार्क्सवादी आज सत्य को भी सत्य प्रमाणित नहीं कर पा रहे।

बुद्धदेव जी ने गोर्बाचोव के कार्यों से सबक नहीं सीखा। गोर्बाचोव के एक काया पलट से सारी दुनियाँ की राजनीति बदल गई, रूस और चीन का भी कायापलट हो गया किन्तु गोर्बाचोव को रूस की जनता की प्रशंसा नहीं मिली। आज भी उन्हे साम्यवाद का विभीषण ही माना जाता है। इसी तरह बुद्धदेव जी ने भारतीय मार्क्सवाद को दुनियाँ की राह चलने का संदेश देकर उसे भारत से विदा करने का रास्ता खोल दिया है। यह कदम उठाने के पूर्व वे यह भूल गये कि भारतीय राजनीति में न्याय और तर्क का दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है। यदि आप कमजोर होंगे तो आपके अपने लोग भी आप पर चील कौवे के समान टूट

पड़ने में जरा भी हिचकेंगे नहीं। अच्छा होगा कि बुद्धदेव जी यथार्थ को समझें अर्थात् यदि वे बंगाल की जनता का आर्थिक विकास करने का दृढ़ निश्चय ही कर लिये हो तो अपने राजनैतिक बलिदान की पूर्व तैयारी करके ही इस दिशा में आगे बढ़ें और मेरी तो यही सलाह है कि जनहित में सत्ता सुख का खतरा उठाने की हिम्मत उन्हें करनी चाहिये।

## निठारी कांड, हमारी पुलिस और समाज

व्यक्ति परिवार और समाज के आपसी सम्बन्धों में अधिकांश की सीमाएं सुपरिभाषित और स्पष्ट होनी आवश्यक हैं। यदि ऐसा न हो तो समाज में ऐसी विकृतियां आनी शुरू हो जाती हैं जो होती है कुछ भिन्न और दिखती है भिन्न। बहुत पुराने समय से ही व्यक्ति, परिवार और समाज के अधिकारों की सीमाएँ बहुत स्पष्ट थीं। इसलिये टकराव कम होते थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने व्यक्ति परिवार और समाज के आपसी सम्बन्धों की व्याख्या का अधिकार शासन को सौंप दिया जिसमें ऐसी अव्यवस्था फैलाई कि व्यक्ति परिवार और समाज के आपसी अधिकारों की सारी सीमाएँ टूट गईं। अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई कि तीनों के बीच अधिकारों का खुला संघर्ष भी शुरू हो चुका है।

अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश में नोएडा के निठारी गांव में दो लोगो ने बीस से पच्चीस तक के बीच की संख्या में लड़के लड़कियों के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी और लाश को काटकर बगल के नाले में फेक दिया। पंजाब के एक गांव में भी एक पूर्व सांसद की बंद पड़ी मिल में बलात्कार के बाद हत्या के चार बच्चों के शव बरामद हुए। लगभग इसी अवधि में उत्तर प्रदेश मेरठ में कविता चौधरी नामक नवयूवती की हत्या होती है जिसमें उत्तर प्रदेश के कई मंत्री तक के वासनात्मक सम्बन्धों का आरोप लगा। पुरे भारत में ऐसी घटनाओं की लम्बी सूची है जिसमें वासना पूर्ति के उद्देश्य से कई प्रकार के गंभीर अपराध किये गये। ऐसी घटनाएँ पहले भी होती रही हैं किन्तु लगातार ऐसी घटनाओं का स्वरूप जघन्य अपराधों की दिशा में बढ़ रहा है और ऐसी घटनाओं तथा अपराधों की मात्रा और प्रतिशत में भी लगातार वृद्धि हो रही है।

ऐसी सभी चर्चित घटनाओं में अपराधी सम्पन्न होता है, राजनैतिक पहुँच वाला होता है पुलिस से अच्छे सम्बन्ध रखता है जब तक मामला राजनैतिक तूल न पकड़ ले तब तक पुलिस ऐसे मामलों में सक्रिय नहीं होती। मीडिया कुछ दिनों तक तो ऐसी घटनाओं की बाल की खाल निकालता है किन्तु नई घटना के वातावरण में गूँजते ही पुरानी घटना नेपथ्य में चली जाती है। ऐसी घटनाएँ कभी सामाजिक बहस का मुद्दा भी नहीं बन सकती क्योंकि वर्तमान समाज में समाज का नेतृत्व समाजशास्त्रियों के हाथ से खिसक कर या तो राजनीतिज्ञों के पास चला गया है या मीडिया के पास।

ऐसी जो भी घटनाएँ प्रकाश में आई हैं उनमें हत्यारे का उद्देश्य सिर्फ वासना पूर्ति मात्र है, हत्या तो उस पूर्ति का सहायक उपादान है। हत्यारे को वासनापूर्ति के बाद हत्या करके लाश को कहीं ठिकाने लगा देना अन्य किसी भी उपाय से कम खतरनाक और कम खर्चीला उपाय दिखा। क्योंकि हत्या के अतिरिक्त अन्य सारे ही उपाय लम्बे समय तक उसे ब्लैक मेल करते रहते। जीवनभर किसी के मुँह खालने के बदले स्वयं को बंधक रखने की अपेक्षा उसे सदा सदा के लिये समाप्त कर देना ही आसान कार्य। फिर आजकल पुलिस और राजनैतिक पहुँच भी इतनी सस्ती है कि मरने वाले गरीब लोगों की आवाज को तो आसानी से किसी दिशा में मोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि वासना पूर्ति के लिये वैश्या अथवा अवैध सम्बन्धों के स्थान पर ऐसे जघन्य हत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं।

ऐसे मामलों का सामाजिक विश्लेषण करने के लिये हमें चार बातों पर विचार करना होगा, (1) ऐसी इच्छाएँ क्यों बढ़ रही हैं? (2) ऐसे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? (3) पुलिस की क्या भूमिका है? (4) समाधान क्या हैं?

एक बिल्कुल सामान्य सिद्धान्त है कि इच्छा और पूर्ति के बीच अन्तर जितना अधिक होता है अपराधों की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। प्राचीन समय में कामेच्छा का जन्म सोलह से अठारह वर्ष की उम्र में और पूर्ति के लिये विवाह चौदह से सोलह तक हो जाता था। विशेष स्थिति के लिये वैश्यावृत्ति पर भी कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं था। वर्तमान समय में इच्छाएँ तो चौदह से सोलह में पैदा होने लगी और पूर्ति के लिये विवाह सामान्यतया 21 से 28 वर्ष में होने लगा। विशेष स्थितियों की व्यवस्था में भी कई प्रकार की कानूनी बाधाएँ खड़ी हो गईं। भूख और भोजन के समय में दूरी बढ़ा दी जाय और चुपके से क्षुधापूर्ति के सभी होटल भी बंद कर दिये जायें तब भोजन की लूट या चोरी के अवसर बढ़ना स्वाभाविक है। सामाजशास्त्र के विषयों में अनाड़ी राजनीतिज्ञ जब टांग फंसाते हैं तब वातावरण बिगड़ने को सिर्फ कानून नहीं रोक सकता। चरित्रहीन लोग जब चरित्रवान दिखने का प्रयत्न करने के क्रम में चरित्र की व्याख्या करने लगें तो परिणाम तो भयंकर होना ही है। जो शासन व्यवस्था बलात्कार और हत्या जैसे अपराध रोकने में सफल नहीं है वह बार बालाओं और वैश्यावृत्ति नियंत्रण के लिये कानून बनाती है। पारिवारिक मामलों में हिंसा के कानून ने कुछ और विसंगतियाँ पैदा की है। आजकल तो बलात्कार की ऐसी परिभाषा बन गई है कि किसी महिला को विवाह का वचन देकर वर्षों साथ रहे और विचार न करे तो वचन भंग के स्थान पर बलात्कार का मुकद्मा होने लगा है। पांच पांच वर्ष सुख पूर्वक स्वेच्छा के साथ रहने वालों पर भी ऐसे आरोप मँने देखे हैं। किसी बांध को बांधने की तत्परता दिखाने वाले यदि अतिरिक्त जल प्रवाह की चिन्ता न करें तो बांध टूटने का खतरा बिल्कुल स्वाभाविक है।

ऐसे मामलों में पुलिस पर भी खुब उँगलियाँ उठाई गईं। पुलिस में भारी भ्रष्टाचार है ये लोग नेताओं से दबे हुए हैं। ये लापरवाह हैं ये लोग गरीबों की ओर ध्यान नहीं देते ऐसे कई आरोप लगे। ये आरोप तो पूरी तरह सच हैं किन्तु आरोप लगा देना तो कोई समाधान नहीं है। एक एक पुलिस वाला कितना खर्च करके नौकरी पाता है और नौकरी काल में भी किस किस को भी हिस्सा देता है यह वही जानता है। मैंने एक बार सर्वेक्षण कराया था तो पाया कि कुल मिलाकर व्यवस्था में भ्रष्टाचार का जो औसत है पुलिस उससे उपर नहीं है। यह भिन्न बात है कि सब लोग पुलिस पर आरोप लगाकर अपनी ईमानदारी सिद्ध करते रहते हैं और पुलिस वाला उत्तर न दे पाता है न देता है वह सोचता है कि यदि पुलिस कि नौकरी करके ही कुछ अतिरिक्त कमाना है तो गालियाँ भी सुननी पड़ेगी और मानवता न्याय आदि आदर्श भी खूँटी पर टांगने होंगे। जो मिडीयाकर्मी आज इतना ज्यादा उछल रहे हैं वे इतने महिनो तक कहाँ थे। पुलिस राजनैताओं से दबी हुई है इसमें कोई नई बात तो नहीं। पुलिस गरीबों की नहीं सुनती यह भी कोई खास बात नहीं। प्रश्न उठता है कि पुलिस गरीबों की सुने भी कैसे? यदि कुल मिलाकर पुलिस की ताकत सौ युनिट है। यदि पुलिस सभी अपराधों की ठीक से विवेचना करे तो उसे दस हजार युनिट शक्ति चाहिये। वह यदि सब गुमशुदा बच्चों की ही खोज करें तो उसे पांच सौ युनिट शक्ति चाहिये। जबकि उसके पास ऐसे मामलों कि लिये दस युनिट शक्ति ही उपलब्ध है। स्वाभाविक है कि पचास बच्चे गायब होंगे तो पुलिस किसी एक में ताकत लगायेगी और वह भी ऐसे मामलों में जहाँ उसे पैसा भी मिले और राजनैतिक दबाव भी हो। उन्चास मामलों में पुलिस रिपोर्ट लिखकर ठंडे बस्तों में डाल देगी। मैं नहीं समझता हूँ कि पुलिस पर आरोप लगाने वाले इसमें क्या नई बात कर रहे हैं? क्या वह गरीब की जाँच करे और अमीर को छोड़ दे या क्या वह लाट्री निकाल कर जाँच करे? पुलिस को यदि एक प्रतिशत ही अपराध पकड़ने की शक्ति है तो वह क्या और कैसे करे यह कोई

बताने वाला नहीं। बार बालाओं पर रोक और घरेलू महिला उत्पीड़न रोकने का कानून बनाने वाले यह क्यों नहीं बताते कि इसका वजन आप उसी षड्यन्त्र सवकमक भ्रष्ट, लापरवाह, अमीर हितैषी पुलिस को देने जा रहे हैं या कुछ नयी योजना है।

इन अपराधों की रोकथाम का न कोई विचार मंथन हो रहा है न प्रयत्न। सभी दूसरों पर आरोप लगाने की दौड़ में आगे निकलने के प्रयास में है। अपराधियों को खुली फांसी देने के पक्ष में नारा लगाने वालों में ऐसे पेशेवर लोग भी आगे दिख रहे हैं जो धनंजय और अफजल गुरु की फांसी के विरुद्ध भी नारा लगा रहे थे। इस समस्या का समाधान तो गंभीर विचार मंथन से ही होगा। मेरे विचार में निम्न मुद्दों पर विचार करना आवश्यक है:-

- (1) पुलिस हस्तक्षेप योग्य कानूनों की समीक्षा करके कानूनों की मात्रा इतना कम कर देना कि समाज में पुलिस का हस्तक्षेप भी घटे और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ जावे।
- (2) पुलिस को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना।
- (3) न्यायालयों द्वारा पुलिस को सहयोगी मानने की जगह सहभागी मानने की प्रवृत्ति का विकास।
- (4) महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध वर्ग के रूप में खड़ा करने की राजनैतिक प्रवृत्ति पर रोक।
- (5) महिलाओं के विशेषाधिकार समाप्त करके समान अधिकार।

### कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर

**प्रश्न:-** पिछले अंकों में आपने लिखा कि सर्वोदय वामपंथ के प्रभाव में आकर अपनी नीतियाँ और कार्य क्रम बना रहा है। मैं भी सर्वोदय कार्यकर्ता हूँ। मुझे तो आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। फिर पहले तो आप ऐसा नहीं लिखते थे किन्तु इधर एक दो वर्षों से ही आप ऐसा क्यों सोचने लगे? कहीं सर्वोदय के साथ होते खट्टे मीठे रिश्तों का तो कोई प्रभाव नहीं है?

**उत्तर:-** सर्वोदय की दो पहचान है (1) विचार, (2) संगठन। गांधी जी के विचारों के आधार पर जो समाज में जन जागृति पैदा करने का प्रयत्न करें वे सर्वोदयी होते हैं। ऐसे सब लोग विचारों के आधार पर गांधी को समाज में स्थापित करने का निरन्तर प्रयत्न करते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो गांधी संस्थाओं सम्पत्ति नाम आदि की व्यवस्था करते हैं। ये लोग संगठन के रूप में होते हैं ऐसे लोगों के विधिवत् बने संगठन का नाम सर्वसेवा संघ है। सर्वोदय से आचरण मुख्य होती है। भारत में लाखों सर्वोदयी हैं जो गांव गांव तक फैले हुए हैं और जिन्हें बाहर के लोग बहुत कम जानते हैं किन्तु संगठन के लोग निश्चित हैं जिन्हें आम तौर पर प्रचार मिला हुआ है।

मेरा अनुभव यह है कि सर्वोदय के लोगों पर वामपंथ का नगण्य प्रभाव है। वह समाज में सत्य अहिंसा, आदर्श समाज रचना खादी आदि रचनात्मक कार्यों में स्वाभाविक रूप से लगा रहता है और यदि सर्व सेवा संघ कोई विशेष आवाहन करे तो उसमें भी लग जाता है। संगठन की स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। उसे अपने सांगठनिक अस्तित्व की चिन्ता करनी पड़ती है और दिखाने के लिये कभी कभी भले ही समाज रचना का भी काम करना पड़े अन्यथा अधिकांश समय जोड़ तोड़ में ही लग जाता है। मैंने सर्वोदय संगठन के वामपंथी प्रभावित होने की बात लिखी है। उसका सर्वोदय संगठन मात्र से ही संबंध है सर्वोदय कार्यकर्ता से नहीं क्योंकि सर्वोदय कार्यकर्ता के आचरण में ऐसी किसी बीमारी का प्रवेश नहीं के बराबर है।

हम यह विचार करें कि भारत में कौन कौन से व्यवहार हैं जो वामपंथ की पहचान माने जाते हैं:-

(1) अमेरिका विरोध ।

(2) इस्लाम समर्थन—इसमें मुख्य रूप से हिन्दूओं को एक पक्ष माना जाता है। और हिन्दू के विरुद्ध अन्य का समर्थन किया जाता है ।

(3) वर्ग निर्माण वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष ।

(4) हिंसा अहिंसा की बहस से दूरी ।

(5) अधिकार केंद्रित शासन प्रणाली ।

मुझे ऐसा लगता है कि आज सर्वोदय अमेरिका विरोध में आगे आगे रहता है मैं सर्वोदय संगठन की जितनी भी बैठकों या सम्मेलनों में गया उसमें घुमा फिराकर इराक और अमेरिका के टकराव की चिन्ता सबसे अधिक दिखती रही। वक्ताओं के भाषणों में भारतीय आतंकवाद का विरोध भरा रहता था। अभी नवंबर माह में बम्बई में “ आतंकवाद की जड़ कहाँ है” विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार सर्वसेवा संघ वैनर तले हुई। इसमें सात आठ वक्ताओं ने भाग लिया जिसमें बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा, कैथोलिक धर्मगुरु डाल्फी डिसूजा प्रसिद्ध समाज सुधारक असगर अली इंजीनियर संसद पर आक्रमण से दोष मुक्त प्रोफेसर गीलानी, अधितक्ता युसुफ मुछाला, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर, संघ परिवार के किशोर जावले ऐसे लोग थे जो सर्वोदय परिवार के नहीं थे। सूची देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने तटस्थ सूची बनी। इस सेमिनार में आयोजकों की ओर से जो प्रस्तावना भाषण दिया गया उसका पूरा का पूरा तथ्य अमेरिका को आतंकवादी प्रमाणित करना था। मुख्य भाषण की शुरुवात “ हम दो फ्रांसियो (सद्दाम और अफजल गुरु) के बीच के अन्तराल में आतंकवाद पर विचार करने के लिये बैठें हैं से हुई। अब आप स्वयं सोचिये कि किस तरह आतंकवाद जैसे मुद्दे को सद्दाम और अफजल की फ्रांसी के बीच केंद्रित कर दिया गया। इसके बाद भाषण में लम्बा अफगानिस्तान ओसामा और इराक का संदर्भ दिया जाता है और अंत तक पूरा भाषण अमेरिका विरोध करते करते समाप्त हो गया। लगा कि हम किसी अन्तराष्ट्रीय सेमिनार में बैठे हों और प्रस्तावक संस्था भी राष्ट्रीय से कही अधिक अन्तराष्ट्रीय आतंकवाद के प्रति गंभीर हो। अफजल गुरु के अपराध को भी वामपंथी चेहरे से ही देखा गया और बाकी सारी कमी पूरी करने के लिये तो प्रोफेसर गीलानी और युसुफ मुछाला जी बैठाए हुए थे ही। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि सम्पूर्ण कार्यक्रम में नक्सलवाद कश्मीरी आतंकवाद या आसाम में आतंकवाद पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। इसी तरह स्वदेशी आंदोलन की भी जो दशा है वह पूरी तरह एक पक्षीय है जिसमें स्वदेशी कि अपेक्षा विदेशी विरोध को अधिक महत्व प्राप्त है। मैं नहीं समझता कि गांधी जी के स्वदेशी का यह अर्थ रहा। मेरे विचार में गुलाम भारत में स्वदेशी का अर्थ भले ही भारतीय हो पर स्वाधीन भारत में स्वदेशी का अर्थ स्थानीय ही होगा। किन्तु वामपंथ के नीति निर्धारण की पहल में हमने अपनी सारी नीतियों को अमेरिका विरोध तक केंद्रित कर दिया।

इसी तरह वामपंथ की दूसरी खास पहचान है इस्लाम का अन्ध समर्थन। वामपंथी संघ परिवार को हिन्दूओं का प्रतिनिधि मानकर संघ परिवार कि गलतियों के लिये आम हिन्दूओं के विचारों कि आलोचना करता है किन्तु मुसलमानों के मामले में उसकी भाषा तत्काल बदल दी जाती है वह मुस्लिम कट्टरवादियों के साथ मुसलमानों को कभी नहीं जोड़ता। प्रोफेसर गीलानी इसलिये निर्दोष है क्योंकि न्यायालय ने बरी कर दिया और अफजल गुरु इसलिये माफी योग्य है कि उन्हें वकील नहीं मिला। ये लोग हिन्दूओं में महिला उत्पीड़न की खुब चर्चा करते हैं किन्तु मुसलमानों में नहीं करते। ये लोग समान नागरिक संहिता तक का विरोध करते हैं। मैंने सर्वोदय के अच्छे से अच्छे लोगों को भी मुसलमानों की एकतरफा चापलूसी करते पाया है। मैं यह दावे के साथ कह

सकता हूँ कि सर्वोदय वालों पर न इस्लाम को कोई प्रभाव है न ही मुसलमानों का कोई दबाव है। इनके मन में संघ के प्रति घृणा है और वामपंथी उस घृणा को इस्लाम समर्थन के रूप में हमेशा भुनाते रहते हैं।

वामपंथ कि तीसरी पहचान है वर्ग संघर्ष। सम्पूर्ण समाज में भिन्न भिन्न आधारों पर वर्ग निर्माण करके उपेक्षित और शोषित वर्गों को अपने अधिकारों के प्रति इस प्रकार जागृत और संगठित करना कि वह जागृति वर्ग संघर्ष का रूप ले सके। सर्वोदय की कभी यह नीति नहीं रही। सर्वोदय की हमेशा नीति रही है कि उच्च वर्गों में इस तरह कर्तव्य भाव जागृत किया जाये कि शोषण समाप्त हो और वर्ग संघर्ष कमजोर हों। जो न माने उन्हें कानून से भले ही मना दिया जाय। किन्तु किसी भी स्थिति में समाज में संघर्ष न हो। किन्तु वामपंथियों के प्रभाव में सर्वोदय निरंतर वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहित करने की नीति पर चल रहा है।

चौथी बात यह है कि समाज में हिंसा अहिंसा के बीच यदि कोई बहस छिड़ी तो अहिंसा का पक्ष न्याय संगत प्रमाणित होना स्वभाविक माना जाता है। साम्यवाद ऐसी बहस को निरूत्साहित करता है वह इराक और अफगानिस्तान की हिंसा का चाहे जो प्रतिरोध करें किन्तु नक्सलवादी हिंसा का विरोध नहीं करता। समाज में भी कानूनी और अहिंसक प्रतिरोध के स्थान पर हिंसक टकराव को वह प्रश्रय देता है। सर्वोदय पूरी तरह अहिंसा का पक्षधर है किन्तु वह हिंसा अहिंसा के बीच स्पष्ट विभाजन में रूचि नहीं रखता। मैंने तो सर्व सेवा संघ के उच्च पदाधिकारियों को भी खुलेआम हिंसा समर्थक आयोजनों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते देखा है।

पांचवी बात यह है कि साम्यवाद केन्द्रित शासन व्यवस्था का पक्षधर है और सर्वोदय विकेन्द्रित शासन व्यवस्था का पक्षधर। किन्तु जय प्रकाश आंदोलन के बाद सर्वोदय के सभी प्रयत्न केन्द्रित शासन व्यवस्था के पक्षधर रहे। केन्द्रित शासन व्यवस्था में दूसरा पक्ष शासन की गलत नीतियों का विरोध करके उसे सुधारने हेतु मजबूर करता है जबकि विकेन्द्रित शासन व्यवस्था में विपक्ष शासन के आदेशों का विरोध न करके अधिकारों को चुनौति देता है। सर्वोदय ने अभी एक नमक आंदोलन पर विचार किया किन्तु वह भी शासन के गलत आदेश को सुधारने कि माँग थी न कि अधिकारों को चुनौती। जब भी सर्वसेवा संघ में अधिकारों के विकेन्द्रीयकरण की बात आती है तो वामपंथी वर्ग किसी न किसी बहाने उसे पीछे करने में सफल हो जाता है।

मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि धर्म निरपेक्षता वर्ग समन्वय अहिंसा अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण सर्वोदय के सामान्य कार्यकर्ता की स्वभाविक सोच है और इन विषयों पर इतनी स्पष्ट सोच किसी अन्य ग्रुप की नहीं है। यह पूरी तरह प्रमाणित है कि किसी भी परिवर्तन के चारों मुल आधार हो सकते हैं अर्थात् भारत में समाजिक परिवर्तन का नेतृत्व सर्वोदय ही कर सकता है और दूसरा स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकता। सर्वोदय का हर कार्यकर्ता इन मामलों में स्पष्ट सोच रखता भी है किन्तु सर्वोदय नेतृत्व वामपंथियों के वाकजाल में फसकर उसे पुँजीवाद विरोध, संघ विरोध, शोषण विरोध, सत्ता की गलत नीतियों का विरोध अधिकारों के लिये हिंसा आदि दिशा में मोड़ रहा है। मेरी इच्छा है कि सर्वोदय कार्यकर्ता अपने नेतृत्व को इस बात के लिये तैयार करें कि किसी अहिंसक और सवैधानिक आंदोलन की दिशा बन सके।

यह एक शुभ संकेत है सर्वोदय का अधिकांश कार्यकर्ता प्रतिनिधि वापसी तथा स्थानीय इकाइयों को अधिकारों की संविधान में सूची होने को ही असली गांधीवाद तो पहले से ही मानता है किन्तु अब इसके लिये संगठित आंदोलन की दिशा में भी सक्रिय हो रहा है। संघर्ष को इधर उधर बहकाने वालों की संख्या लगातार घट रही है। भविष्य में इस दिशा में और भी अधिक ध्रुवीकरण

की पूरी पूरी संभावना है। हमारा पूरा प्रयत्न होगा कि ऐसे लोगों से मिलकर हम निरंतर उसके हृदय परिवर्तन का प्रयास जारी रखेंगे।

## प्रश्नोत्तर

(1) श्री बी. एन. मुदगिल, प्रेस सदन, गद्दीखेड़ी, रोहतक, हरियाणा।

ज्ञान तत्व मिला। आपके बजरंग अग्रवाल से बजरंग मुनि हो जाने पर मेरी बधाई स्वीकार करे। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के लिये आपका यह मानसिक परिवर्तन बहुत अच्छा लगा। विश्वास है कि अब आप अधिक तन्मयता से व्यवस्था परिवर्तन के कार्य में लग सकेंगे।

**उत्तर:**—आश्रम व्यवस्था समाज शास्त्र की व्यवस्था है धर्म या आध्यात्म की नहीं। वर्तमान समय में वानप्रस्थ या सन्यास के दो अर्थ माने जाते हैं (1) आध्यात्म की ओर प्रवृत्ति और (2) समाज सेवा। आध्यात्म मनुष्य को आत्मकेन्द्रित, समाज से दूर, अगले जन्म की चिन्ता और समाज में किसी प्रकार की समस्या पैदा न करने की दिशा में बढ़कर मुक्ति की प्रतिक्षा में लगाये रखता है। दूसरी ओर समाज सेवा मनुष्य को समाज केन्द्रित इसी जन्म की चिन्ता और समाज की समस्याओं के समाधान में सक्रिय होने का मार्ग है। मैंने वानप्रस्थ के माध्यम से पहला मार्ग न चुनकर दूसरी मार्ग चुना है जिसका अंतिम पड़ाव सन्यास है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं वानप्रस्थ के अपने कीमती समय में धन, पद, राष्ट्र और धर्म की रूढ़ियों से उपर उठने की अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर लूँ जिससे कि मेरा अंतिम पड़ाव समाज के लिये अधिक से अधिक उपयोगी संभव हो सके। मेरा यह अनुभव है कि अनेक सन्यासी भी स्वयं को धन या पद की दौड़ से मुक्त नहीं कर पाते। धर्म के सांगठनिक स्वरूप से मुक्त होना तो और भी कठिन होता है। सन्यासी को तो हिन्दू मुसलमान इसाई का भेद भी छोड़ना होता है। क्योंकि चोटी यज्ञोपवीत आदि की पहचान से भी वह मुक्त होकर सम्पूर्ण मानव समाज को अपना मानना शुरू कर देता है। मेरा प्रयत्न यही है कि मैं आप सबकी आशाओं को पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त कर सकूँ।

(2) धनबाद महिला मंच, धनबाद, झारखंड।

आचार्य राममुर्ति ने शिक्षा को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की आवाज उठाकर एक उचित कदम उठाया है। शिक्षा को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना ही चाहिये। आज से चालीस वर्ष पूर्व शिक्षा देने का काम समाज के द्वारा होता था और सरकार का इसमें सहयोग भी था। फिर सामाजिक नियंत्रण वाली शिक्षा व्यवस्था को सरकारी नियंत्रण—यानि अफसर इन्स्पेक्टर के जिस्में क्यों कर दिया गया? घण्टा आधारित काम एवं महीना आधारित तनख्वाह (मजदूर की मजदूरी के तर्ज पर) वाले वेतन भोगी शिक्षकों से जीवन की शिक्षा (नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आदि) संभव है क्या? इसी सरकारी शिक्षा और उसकी व्यवस्था के कारण आज का शिक्षित नौजवान श्रम और उत्पादन करने वालों से नफरत करता हूँ और मौजमस्ती से जीने वाले सफेदपोश पेशेवर नेता—अफसर—बाबुओं को सलाम करता है।

श्रम से कोसों दूर अंग्रेजों के जमाने की लोर्ड मैकाले वाली अफसर बाबू बनाने वाली शिक्षा को बदलना था लेकिन भारत के मूर्ख एवं भ्रष्ट राजनीतिज्ञों ने शिक्षा व्यवस्था को सरकारी नियंत्रण (केन्द्रीकरण एवं एकाधिकार) में बदलकर शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था दोनों तरीकों से समाज को सरकार पर आश्रित बना दिया। इससे समाज अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होकर पंगु बन गया। सरकार का खर्च सरकार की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण पद्धति पर किसी भी निजी विद्यालय से बहुत अधिक होने के बावजूद

इतना खराब है कि मजबूरी को छोड़कर कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को ऐसी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिये भेजने की बजाय फीस लेने वाली किसी निजी या सामुहिक विद्यालय में भेजना ज्यादा पसन्द करता हैं। इस सरकारी शिक्षा व्यवस्था का अन्ततोगत्वा परिणाम यह हुआ कि हर गाँव शहर सभी जगह लाभ कमाने वाली निजी शिक्षा व्यवस्था कुकूरमुत्ते की तरह फैल गई है। इतनी कमजोर शिक्षा व्यवस्था के चलते इससे न कोई रवीन्द्रनाथ टैगोर और न कोई विनोबा भावे बन रहें हैं बल्कि भारत दिनों-दिन कमजोर हो रहा है और बाजार आधारित अर्थ व्यवस्था समाज पर हावी हो गई है।

समाज के लिये जरूर पानी, बिजली, सड़क, शौचालय, चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, कम्प्यूटर,, गाड़ी आदि सभी वस्तुएँ विज्ञान के अविष्कार से जुड़ी है और विज्ञान शिक्षा का ही विषय है, हिस्सा है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी समाज का एक हिस्सा है, सरकार का नहीं। कब, कैसी और किस प्रकार की शिक्षा मनुष्य को चाहिये या , देनी है उसे समाज से बेहतर कौन समझ सकता है इसलिये शिक्षा देने की जिम्मेदारी हर हाल में समाज की ही होनी चाहिये।

क,ख,ग (प्राथमिक) की शिक्षा हो या ज्ञान, हुनर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है। शिक्षा देने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है शिक्षक (त्यागी, तपस्वी, ज्ञान, हुनरवान) बनाने का। इस काम को भी सिर्फ समाज ही खोज सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है या फिर ऐसे लोगों को बना सकता है। सरकारी नौकरी में सिर्फ एम.ए, बी.ए वाली पढ़ाई का मापदण्ड होता है त्यागी, तपस्वी से उसे कोई लेना देना नहीं होता है। वैसे शिक्षा देना कोई रोजगार देना या बेरोजगारी दूर करने या फिर कमाई करने का जरिया कभी नहीं होना चाहिये। समाज अपने त्यागी, तपस्वी, तजुर्बेकार, हुनरवान लोगों को इज्जत कर सम्मान देता है। अगर ऐसे लोग शिक्षा देने यानि शिक्षक का काम करेंगे तभी जीवन की शिक्षा का महत्वपूर्ण आयाम पूरा होगा।

जीवन पैसा सरकार शिक्षा में खर्च कर रही है, अगर वह पैसा सरकार सीधा अपने खर्च न कर समाज के माध्यम से खर्च करे तो आज भारत में जो अशिक्षितों की फौज (लगभग एक तिहाई) है, वह समाप्त हो जायेगी। देश पूर्ण साक्षर हो जायेगा। इसके लिये न विदेशी शिक्षा की जरूरत होगी, न विदेशी पैसे की।

शिक्षा समाज की जरूरत है, इसमें सरकार का दखल नहीं होना चाहिये बल्कि जिस प्रकार न्यायपालिका का पूरा खर्च सरकार वहन करती है और न्याय देने में दखल नहीं देती है उसी प्रकार शिक्षा का भी सारा खर्च सरकार को उठाना चाहिये और दखल नहीं देना चाहिये।

क्रान्ति व्यक्ति या समाज की सोच के आधार पर यथास्थिति को तोड़ती है उसमें आमूल चूल बदलाव लाती है। जबकि बदलाव बिना सोचे समझे हालात के अनुसार प्रक्रियागत चलते रहता है।

आइये हमसब मिलकर सोच समझकर शिक्षा को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर कई दिशा दें ताकि भारत में व्याप्त असंख्य समस्याओं का समाधान लोगों को जागरूक बना कर किया जाये जिससे शिक्षा जीवन शैली बन जाये।

उत्तर:- मैं आपकी इस मांग से सहमत हूँ कि शिक्षा को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाय। मैं सहमत हूँ कि सरकार अपना शिक्षा बजट स्वतंत्र शिक्षा पर ही खर्च करे। मेरी इतनी मांग अवश्य है कि शिक्षा पर खर्च होनेवाले बजट का अधिकतम खर्च अशिक्षितों पर किया जाय और उसका कोई भी टैक्स ग्रामीण गरीब अशिक्षित पर न लादा जाय। यदि बिना अशिक्षितों पर टैक्स लगाये शिक्षा का खर्च पूरा न हो तो भी अशिक्षित गरीब ग्रामीण श्रमजीवियों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता भले ही शिक्षा का खर्च पूरा हो या न हो।

(3) श्री सत्यदेव गुप्त सत्य, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

मैंने बारह वर्ष पूर्व उस समय का आजीवन सदस्यता शुल्क एक सौ इक्कावन रुपये जमा करके सदस्यता ली थी। ज्ञान तत्व तो मुझे बराबर मिल रहा है। किन्तु मेरा नाम आजीवन की सूची में नहीं है। क्या मुझे फिर शुल्क देना होगा?

**उत्तर:—**एक वर्ष पूर्व हम लोग शुल्क की न कोई चिन्ता करते थे न ही रिकार्ड रखते थे। अब एक वर्ष से दिल्ली आने के बाद हिसाब भी शुरू हुआ है और चिन्ता भी। इसीलिये हमने सूची प्रकाशित की है कि ऐसे छूटे नाम शामिल हो सकें। आपका नाम जोड़ दिया है। और भी किन्ही का नाम छूट गया हो तो खबर करियेगा। एक सौ इक्कावन वाली भी सूची पूरी तरह मान्य है। क्योंकि आप सबका वैचारिक सहयोग पैसे से कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है।

(4) श्री एम. एस. सिंगला, अजमेर, राजस्थान।

ज्ञान तत्व 117 में आपका लेख मंहगाई का सच पढ़ा यह सहमति है कि मंहगाई और मुद्रास्फीति एक सिक्के के दो पहलू हैं। मेरे विचार में मंहगाई की तीन अवस्थाएँ हैं:—

(1) जब पांचवे दशक में द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम स्वरूप वस्तुएँ कम मिलती थी और दाम अधिक लगता था।

(2) छठे दशक के बाद मुद्रा के साथ छल किया गया। पहले कुल मुद्रा का तैंतालीस प्रतिशत मूल्य का सोना रखना आवश्यक था जिसे बाद में संशोधित किया गया। परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में नोट छापने के द्वार खुले जिसके कारण मंहगाई किशोरावस्था में आ गई।

(3) वर्तमान स्थिति है जिसमें मंहगाई तेज गति से बढ़ रही है। अब आप इसे चाहे मंहगाई कहें या मुद्रा स्फीति।

मुद्रा स्फीति के आकलन का वर्ष भी प्रति दस-बीस वर्ष में बदल जाता है। जिससे कुछ पता ही न चलें। सन सैंतालीस की तुलना में रुपये का मूल्य सिर्फ पांच पैसा ही बचा है जबकि चांदी का रुपया दो सौ तेइस रुपया के बराबर है।

**उत्तर:—**आपने जो तीन अवस्थाएँ बताई हैं उनका भारत के आम लोगों पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं यह स्पष्ट करें। मेरे विचार में किसी मुल्लू वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न अच्छा न बुरा। प्रभाव तो तब पड़ता है जब उसकी क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़े। आपने स्वयं एक ग्रामीण का उदाहरण दिया जिसके अनुसार उसे गाँव में अनाज के बदले मिलने वाले सामान में कोई फर्क नहीं दिखता।

अपने सैंतालीस के रुपये के बदले आज पांच पैसा बताया। मेरी जानकारी अनुसार सन् सैंतालीस के मुकाबले अब रुपये का मूल्य दो पैसे से भी कुछ कम 1.91 पैसे ही बचा है। आप एक बार और पता करियेगा। सन् सैंतालीस में दो पैसे का जितना अनाज मिलता था आज एक रुपये का उससे बहुत अधिक मिलता है अर्थात् अनाज सस्ता हुआ है इससे उपभोक्ताओं में स्पष्ट सुधार और किसानों में कमजोरी दिख भी रही है। इन सबमें मंहगाई का कोई प्रभाव न होते हुए भी पूँजीवादी लोग आर्थिक असमानता पर से ध्यान हटाने के लिये मंहगाई का मुद्दा खड़ा करते हैं।

मेरे मित्रों ने मुझे समझाया है कि मंहगाई का मुद्दा इतनी गहराई तक आम लोगों के मन में बैठा है कि वह निकलना बहुत कठिन है। बल्कि इस मुद्दे पर बहस चलाने से हमारे आंदोलन पर विपरीत प्रभाव होगा। मैं उनके इस निष्कर्ष से सहमत हूँ इसीलिये हमारे आंदोलन में यह मुद्दा शामिल नहीं है। और मैं इस मुद्दे पर ज्यादा जोर भी नहीं देता किन्तु वर्ष में एक दो बार अपने साथियों को सतर्क करना आवश्यक है कि वे ऐसे असत्य मुद्दे उठाने से बचें। यही सोचकर कभी कभी मंहगाई और मुद्रास्फीति पर ज्ञान तत्व में कुछ चर्चा हो जाया करती है।

(5) श्री किशोर चौधरी, गजासराय, इस्लामपुर, नालंदा, बिहार।

ज्ञान तत्व पढ़ता हूँ। बहुत सुलझे हुए और सतुंलित विचार मिलते हैं। आतंकवाद पर और अधिक गंभीर आक्रमण की आवश्यकता है। राजनैतिक दल तो मुसलमानों की खुली आलोचना से डरते हैं। जबकि अब तो आतंकवाद और इस्लाम का संबंध जग जाहिर प्रमाणित हो चुका है। भारत के मुसलमान आतंकवाद को छिपा कर रखते हैं जो उनके लिये बदनामी का कारण होता है।

(6) श्री अमरचन्द शर्मा, वैशाली नगर, अजमेर, राजस्थान।

ज्ञान तत्व में प्रकाशित लेख "आतंकवाद कारण और निवारण" पढ़ने को मिला लेख से अनेक नये तथ्य प्रकाश में आये। ऐसे गंभीर विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने चाहिये।

(7) श्री रविन्द्र सिंह तोमर, गुना, मध्य प्रदेश।

संघ को जहाँ तक मैं समझा हूँ वहाँ तक ये लोग सामाजिक प्रदूषण फैलाते रहते हैं। इनके सारे काम गुप्त होते हैं। सच भी है कि हिंसक अतिवादी लोग गुप्त काम करने के ही अभ्यस्त होते हैं। इन्होंने गोडसे जैसे हिंसक व्यक्ति और उसकी विचारधारा को प्रोत्साहित किया है। इन लोगों ने बड़ी संख्या में मुसलमानों और दलितों को अनावश्यक जेल में बंद करके रखा हुआ है। अपूर्वानन्द जी के जिस लेख का जिक्र आपने किया है वह पाठकों को खुली बहस के लिये भेजना उचित प्रतीत होता है।

उत्तर:—आपने संघ के विषय में जो कुछ समझा है उससे मैं सहमत हूँ। यह सच है कि ये अतिवादी होते हैं। ये समाज में अपना आदर्श थोपते रहते हैं। ये अपने को हिन्दू धर्म और भारतीय संस्कृति का स्वाभाविक ठेकेदार मानते हैं। किन्तु आपने जो समझा वह बिल्कुल अधूरा है। आपने यह नहीं समझा कि संघ का जैसा स्वभाव है इस्लाम का स्वभाव उससे कुछ अधिक ही वैसा है। मुसलमानों की संख्या जेलों में अधिक है यदि यह सच है तो बहुत ही शर्म की बात है अन्य मुसलमानों के लिये भी। मुसलमानों और दलितों को संघ के लोगों द्वारा जेल में बंद कराने का आपका तर्क इसलिये अर्थहीन है कि संघ विरोधी राज्यों में भी इनकी संख्या अधिक क्यों है? महाराष्ट्र में इनकी संख्या अधिक क्यों है? जब भी कोई मुसलमान आतंकवादी पकड़ा जाता है तो सभी धर्म निरपेक्ष लोग भी अंत तक उनके निर्दोष होने का वातावरण बनाने में क्यों लगे रहते हैं? धर्म निरपेक्षों कि मुस्लिम आतंकवादियों के साथ होने वाली स्वाभाविक सहानुभूति को भी यदि आपने समझा होता तो आपको समझने में मुझे अधिक सुविधा होती।

आज ही मैंने समस्थ नामक पत्रिका का नवंबर दिसम्बर अंक पढ़ा पत्रिका के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि उसने तो मालेगांव बम विस्फोट कांड तथा बम्बई रेल धमाका काण्ड में बजरंगदल का हाथ सिद्ध करने का भरपूर प्रयास किया है। पत्रिका में कई जगह इस प्रयास के लिये काफी खींचतान भी की है। किन्तु इस पत्रिका में प्रसिद्ध समाज शास्त्री असगर अली इंजीनियर का नाम पढ़कर चौंक गया। उनके विषय में मेरी धारणा एक वास्तविक धर्म निरपेक्ष की रही है। सर्वोदय के अधिवेशनो में उन्हें समझने का अवसर भी मिला। किन्तु इस पत्रिका में छपा देखकर कि इंजीनियर जी भी मालेगांव बम विस्फोट कांड में संदेहास्पद मुस्लिम आरोपियों के पक्ष में इस सीमा तक आगे बढ़े कि उन्होंने अपने कथन के पक्ष में पुलिस की निष्पक्षता पर भी आरोप लगा दिये। मैं अब भी समझता हूँ कि असगर अली इंजीनियर जी ने या तो आरोपियों के पक्ष में खड़े होने की जल्दबाजी करके भूल की अथवा असगर अली जी के कट्टर मुस्लिम फिरका परस्त चेहरों को धर्म निरपेक्ष समझने की मैंने भूल की। कहीं तो भूल अवश्य हुई है अब जब पुलिस जांच में सिद्ध हो चुका है कि बम विस्फोटों में आतंकवादी मुसलमानों का ही हाथ था,

बलरंगदल का नहीं तो इंजीनियर जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। मेरे एक मित्र उग्रनाथ जी नागरिक लखनऊ वाले के विषय में मेरी बहुत अच्छी धारणा है। मैं उनकी सत्य शोधन धारणा का प्रशंसक हूँ। उन्होंने भी इंजीनियर जी की बहुत प्रशंसा की थी। मैं इस संबंध में उनके भी विचार जानना चाहूँगा।

मेरा रवीन्द्र सिंह तोमर जी से विशेष आग्रह है कि वे धर्म निरपेक्षता की ठीक ठीक परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो और अधिक अच्छा होगा। हिन्दू होते हुए भी संघ की आलोचना और इस्लाम की चापलूसी को धर्म निरपेक्षता कहने के दिन अब नहीं रहें। ऐसे धर्म निरपेक्षों की पोल खुलने लगी है। अब तो भारत में धर्म निरपेक्षता का वह स्वरूप सामने आ रहा है। जिसमें सभी साम्प्रदायिक शक्तियों को एक मंच पर खड़ा करके उनके विरुद्ध बिना हिन्दू मुसलमानों इसाई का भेद किये सभी धर्म निरपेक्षों को खड़ा किया जायगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस धर्म निरपेक्ष समूह को नकली धर्म निरपेक्षों से मुक्त ही रखा जायगा। आशा है कि तोमर जी हमारे साथ रहेंगे।

(8) श्री एम. एस. सिंगला, अजमेर, राजस्थान।

ज्ञान तत्व 120 में आपने आचार्य पंकज जी तथा ठाकुरदास जी बंग के गंभीर और नाजुक प्रश्नों का बहुत गंभीर, संयम और शालीनता का उत्तर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। आचार्य पंकज जी ने यात्रा का जो विवरण प्रस्तुत किया वह भी सहज, सरल और स्वाभाविक था। बहुत अच्छा लगा।

श्री शंशाक मिश्र भारती पिथैरागढ़ ने आपसे प्रश्न किया था कि “पंथ निरपेक्ष भारत में ऐसे लोगों के विचारों की भी गंभीरता से चिन्ता की जाती है जो राष्ट्र से भी बड़ा धर्म या पंथ का मानते हैं। धर्म की व्याख्याओं की आड़ में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगीत आदि को पीछे ढकेल दिया जाता है। संभवतः यह सब वोट की राजनीति है श्री भारती जी के प्रश्न का आपने उत्तर किसी कारण से टाल दिया। इस विषय पर आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा रहेगी। इस संबंध में मैंने पूर्व में अपने विचार भेजे थे। यदि छपे होते तो यह प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर:**—आपने ऐसा कोई लेख भेजा जो नहीं छपा। कोई परिस्थिति हो सकती है। शंशाक जी का उत्तर मैंने व्यस्तता के कारण नहीं दिया था। क्योंकि दो माह की यात्रा के बाद व्यस्तता अधिक थी।

धर्म, राज्य, राष्ट्र और समाज शब्दों की कोई निश्चित परिभाषा का अभाव जटिलताएँ उत्पन्न करता है। धर्म के दो प्रकार के अर्थ होते हैं (1) सांगठनिक (2) आचरण से जुड़ा हुआ। हिन्दू लोग धर्म का आचरण प्रधान अर्थ मानते हैं और इस्लाम संगठन प्रधान। संघ परिवार परिस्थिति अनुसार अर्थ बदलता रहता है। प्रचार में वह आचरण प्रधान अर्थ को महत्व देता है और व्यवहार में संगठन प्रधान को।

राष्ट्र और धर्म के बीच विचार करें तो यह तय करना कठिन है कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। महत्व का निर्धारण करने के पूर्व समाज और धर्म के सम्बन्धों पर भी सोचना होगा तथा समाज और राष्ट्र के सम्बन्धों पर भी। समाज को अलग थलग करके राष्ट्र राज्य और धर्म के सम्बन्धों पर विचार मंथन केन्द्रित करना घातक होगा। दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया में यही हो रहा है और भारत भी इसी विवाद में उलझा हुआ है। इस्लाम धर्म सर्वोच्च का नारा दे रहा है और संघ राष्ट्र सर्वोच्च का। आप भी कहीं न कहीं एक के साथ खड़े हैं जबकि समाज सर्वोच्च है और राष्ट्र उसका एक अंग है राज्य उसका सहायक है और धर्म उसका मार्ग दर्शक है। अंग सहायक और मार्गदर्शक तीनों मूल पर ही नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं जो घातक है। मैं चाहता हूँ कि आप इस

दिशा में विचार मंथन को आगे बढ़ाने में मेरी कुछ मदद करें तो अच्छा होगा। आप पाठकों की राष्ट्र, राज्य, धर्म, और समाज के सम्बन्धों पर गंभीर विवेचना की मैं प्रतीक्षा करूँगा।

(1) श्री बी. एन. मुदगिल, प्रेस सदन, गद्दीखेड़ी, रोहतक, हरियाणा।

(2) धनबाद महिला मंच, धनबाद, झारखंड।

(3) श्री सत्यदेव गुप्त सत्य, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

(4) श्री एम. एस. सिंगला, अजमेर, राजस्थान।

(5) श्री किशोर चौधरी, गजासराय, इस्लामपुर, नालंदा, बिहार।

(6) श्री अमरचन्द शर्मा, वैशाली नगर, अजमेर, राजस्थान।

(7) श्री रविन्द्र सिंह तोमर, गुना, मध्य प्रदेश।

(8) श्री एम. एस. सिंगला, अजमेर, राजस्थान।

(8) श्री रमाशंकर पाण्डेय ई-763, सोनारी, जमशेदपुर झारखंड।

नव सृजन, नव चिन्तन

नव चेतना, नव हर्ष।

आप को सुख शान्ति

और समृद्धि दे नव वर्ष।।

अंक 123 मिल। वानप्रस्थ की भी सूचना मिली। लिखों कि तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है जो वानप्रस्थ की सोच बनी। तुम्हारे अंदर समाज अनेक महापुरुषों की आत्माओं का दर्शन कर रहा है। तुमसे समाज को बहुत उम्मीदें हैं। मैं तो अब उम्र के अंतिम चरण में हूँ। शरीर थक गया है। बताओं तुम्हारी क्या और कैसे मदद करूँ।

**उत्तर:**—मेरी उम्र 68 वर्ष की हुई है। मुझे कुछ वर्ष पूर्व ही वानप्रस्थ लेना चाहिये था जो नहीं ले सका। मैंने यह महसूस किया कि मैं जिस सूत्र में समस्याओं का समाधान समझ रहा हूँ। वह सफल होना आवश्यक होते हुए भी कठिन काम है। इस कार्य के लिये बिखरे हुए प्रयत्नों की अपेक्षा एकाग्र प्रयत्न की आवश्यकता है। पारिवारिक सम्पत्ति और सामाजिक पद एकाग्रता को क्षति पहुँचाते हैं। इसलिये मैंने वान प्रस्थ की घोषणा की कि यह बाधा दूर हो सकें। अब मुझे अपना सारा समय इस आंदोलन को सहायता और मार्गदर्शन में लगाने में सुविधा होगी। आप लोग मुझसे जैसी अपेक्षा रखते हैं मैं आप सबकी अपेक्षाओं को पूरा करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूँगा। आपका स्वास्थ्य और उम्र के आधार पर आप हमें आर्शीवाद दें कि हम इसी प्रकार ठीक दिशा में आगे बढ़ते रहें।

(9)श्री विश्वनाथ सिंह, हिल्सा, नालन्दा, बिहार।

ज्ञान तत्व 118 में आपने फिर कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन से ही चरित्र सुधरेगा। व्यवस्था न सुधरे तो चरित्र नहीं सुधर सकता। विश्व का अनुभव बताता है कि केवल बाहरी व्यवस्था के ही बदलाव से आन्तरिक परिवर्तन संभव नहीं होगा। बिहार में नीतीश सरकार ने व्यवस्था ठीक की किन्तु परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि व्यवस्था से चरित्र नहीं बदलता। मेरे विचार में चरित्र को धर्म आध्यात्म आदि से ठीक करना संभव है।

**उत्तर:—**भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत का सम्पूर्ण समाज हो विपरीत प्रचारों से गुमराह हो रहा है (1) व्यवस्था से चरित्र निर्माण होता है (2) व्यवस्था से चरित्र नहीं बनता बल्कि हृदय परिवर्तन से चरित्र बनता है। ये दोनों ही बातें आज की समस्या बनी हुई हैं। भारत में राजनैतिक व्यवस्था के माध्यम से चरित्र निर्माण के प्रयास हो रहे हैं। संसद, संविधान और कानून का व्यक्ति के व्यक्तिगत पारिवारिक और सामाजिक जीवन में बिल्कुल भीतर तक प्रवेश हो चुका है। सच्चाई यह है कि सत्ता से चरित्र बनता ही नहीं है। सत्ता तो दुष्चरित्रों पर नियंत्रण का एक तात्कालिक माध्यम है। जिस तरह गाड़ी में ब्रेक होता है उसी तरह विशेष स्थिति के लिये सत्ता का उपयोग है। चरित्र निर्माण तो समाज का कार्य है सरकार का नहीं। जो लोग सरकार के माध्यम से चरित्र निर्माण की बात करते हैं वे गलत हैं। दूसरा पक्ष उनका है जो सरकार पर अंकुश लगाये बिना ही चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं जिस तरह ब्रेक हटाये बिना ही एकसीलेटर से गाड़ी चलाने का गलत प्रयास होता है। जब तक शासन मुक्ति नहीं होगी तब तक चरित्र निर्माण संभव ही नहीं है साठ वर्षों के स्वतंत्र भारत में सत्ता ने भी लगातार चरित्र बनाने का प्रयास किया किन्तु लगातार चरित्र गिरा क्योंकि सत्ता का अनावश्यक हस्तक्षेप ही तो चरित्र पतन का कारण रहा। दूसरी ओर इतने बड़े-बड़े धर्माचार्यों, समाज सुधारकों आध्यात्मिक संतो और आर्य समाज, गायत्री परितार, गांधीवादियों ने सारी शक्ति लगाकर चरित्र निर्माण भी किया और समाज सुधार भी किन्तु परिणाम विपरीत ही हुआ क्योंकि नाव पेड़ से बंधी है और ये लोग दिन रात मेंहनत करके चप्पू चला रहे हैं। मुझे आप लोगों के तर्क सुनकर दया आती है। आप कह रहे हैं कि चरित्र निर्माण व्यवस्था का काम नहीं तो मैं आपसे असहमत कहों हूँ। मैं तो आपसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप चरित्र निर्माण के प्रयत्नों कि अपेक्षा “शासन द्वारा चरित्र निर्माण” के प्रयत्नों से समाज को मुक्त कराने की पहल करें। तब चरित्र बिगाड़ने वाली फैक्ट्री तो बंद होगी और चरित्र निर्माण का प्रभाव दिखेगा अन्यथा जिस तरह साठ वर्ष आप सबने बिता दिये उसी तरह अपने जीवन के कुछ शेष वर्ष और बिता देंगे और समाज का चरित्र निरंतर गिरता जायगा। मेरे विचार में आप जैसे लोगों को चरित्र पतन के लिये अपना दोष स्वीकार करना चाहिये।

बहुत प्रयत्नों के बाद अब राह साफ दिखनी शुरू हुई है व्यवस्था परिवर्तन अभियान चरित्र निर्माण के कार्य से राज्य और सरकार को हटाकर समाज को आगे लाने का पक्ष धर है किन्तु इस बात का पक्षधर बिल्कुल नहीं कि राज्य समाज में लगातार हस्तक्षेप करता रहे और हम राज्य को हस्तक्षेप करने से न रोकें। यदि गांधी आप जैसे लोगों की बात मान लेते तो भारत कभी आजाद ही नहीं होता क्योंकि आप लोग के शासन मुक्ति के लिये संघर्ष के मार्ग को छोड़कर चरित्र निर्माण और ग्राम स्वराज्य की बात कर रहे हो।

## उत्तरार्ध

दिनांक 28 जनवरी 2007 को ग्यारह बजे से बैठक प्रारंभ हुई। चर्चा इस प्रकार हुई:-

(1) **संकल्प पत्र** - कुल एक लाख संकल्प पत्रों के स्थान पर सिर्फ बारह हजार ही संकल्प पत्र प्राप्त हुए। तय हुआ कि इस संबंध में आचार्य पंकज जी, अशोक भाई आगरा तथा सूरी जी मिलकर आगे का कार्यक्रम बनायेंगे। आज की बैठक में विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से तीनों की उपस्थिति नहीं था।

(2) भारत में कई क्षेत्रों से संविधान सभा की मांग उठ रही है। संविधान सभा की मांग करने वाले अधिकांश वे लोग हैं जो शासन के और अधिक हस्तक्षेप के पक्षधर हैं। ऐसा ही संविधान संशोधन का प्रयास राजग सरकार के भी कार्यकाल में हुआ था जिसका हमने विरोध किया था। हमारा उद्देश्य संविधान संशोधन नहीं है। हमारा उद्देश्य लोक स्वराज्य है, जो सिर्फ दो संशोधनों से ही संभव है। यदि दो संशोधनों के साथ कुछ अन्य संशोधनों पर भी विचार मंथन होता है तो हम ऐसी कोशिश के लिये सहमत हो सकते हैं किन्तु दो संशोधनों से दूर यदि संशोधनों पर विचार हेतु कोई संविधान सभा बनती है तो वह हमारे लिये बेकार का प्रयास है। एक बार गांधी जी को संविधान सभा ने धोखा दे दिया है। हम सब संविधान सभा से दूबारा धोखा नहीं खा सकते। अपने सभी साथियों को सतर्क रहना चाहिये। हम संविधान सभा के गठन की न मांग कर रहे हैं न ही हमें उस पर विश्वास है। हमें जन जागरण पर विश्वास है। दो सूत्रों पर हम जनमत खड़ा करके संविधान संशोधन हेतु संविधान सभा का हम गठन करने का प्रयास करेंगे। संविधान सभा सिर्फ दो सूत्रीय संशोधन का माध्यम होगी न कि संविधान संशोधन का आधार।

(3) सितम्बर आठ में हम एक लोक संविधान सभा का गठन करके उसमें दो सूत्रीय संशोधन सहित अन्य संशोधनों पर एक माह तक विचार मंथन करेंगे। इस सभा की प्रारंभिक सूची बननी शुरू हो चुकी है जिसके कुछ प्रस्तावित नाम इस अंक में जा रहे हैं। अन्य नामों के प्रस्ताव आप यथा शीघ्र भेजें जिससे सूची को अंतिम रूप दे सकें। लोक संविधान सभा की सूची को अंतिम रूप एक ग्यारह लोगों की समिति देगी जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार राम बहादूर जी राय करेंगे।

(4) गंभीर विचार मंथन के बाद तय हुआ कि यदि छण्डाण्ड अर्थात् ण्डजपवदंस। ससपंदबम वित स्वातंत्र डवअमउमदज जैसा कोई प्रयास होता है तो हमारे सब साथी उसका पूरा पूरा सहयोग करेंगे भले ही ऐसा प्रयास कोई भी संस्था या संगठन क्यों न करें। ऐसे मूवमेंट में दो संविधान संशोधन आवश्यक रूप से रहेंगे ही।

(5) एक अप्रैल रविवार को 11 बजे से आर्य समाज मंदिर हनुमान रोड, कनाट प्लेस दिल्ली में एक विशेष मीटिंग रखी जाय जिसमें आर्य समाज के प्रमुख लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जावे। इस मीटिंग की अध्यक्षता ब्रह्मचारी राजसिंह जी आर्य करेंगे। दो बजे के बाद अपनी मासिक बैठक वहीं सम्पन्न होगी।

(6) 24 फरवरी को अपनी संरक्षण सभा की बैठक मेवाड़ इन्स्टीट्यूट 4 सी, वसुन्धरा गाजियाबाद में सम्पन्न होगी। इस बैठक में वर्षभर का बजट बनेगा, तथा अगले वर्ष के लिये संरक्षण सभा के अध्यक्ष का चुनाव भी सम्पन्न होगा।

(7) लोक स्वराज्य मंच अपना पूरा आंदोलन दो सूत्रों पर केन्द्रित करेगा।

(1) निर्वाचित जन प्रतिनिधि की वापसी की संवैधानिक व्यवस्था।

(2) राज्य के अधिकारों की अंतिम सूची के बाद शेष अधिकारों को परिवार तथा अन्य इकाइयों में वितरित करके उनकी सूची का संविधान में समावेश करना। तीसरा मुद्दा दूसरे मुद्दे के साथ कभी कभी भ्रम पैदा करता है क्योंकि नीति निर्देशक

सिद्धान्तों के कई प्रावधान तो परिवार, क्षेत्र, जिला, प्रदेश या राज्य के विषय हो सकते हैं, राज्य के नहीं? फिर हम उन सबको बाध्यकारी बनाने की मांग क्या करें? इसीलिये हमने व्यवस्था परिवर्तन अभियान के तीसरे मुद्दे में भी सुधार कर नीति निर्देशक तत्वों के साथ आवश्यक शब्द जोड़ दिया था। चौथा मुद्दा उचित और आवश्यक है किन्तु लोक स्वराज्य मंच के किसी सम्मेलन द्वारा स्वीकृत नहीं है और न ही उसे जोड़ना बहुत अधिक प्रभावकारी ही है।

(8) महसूस किया गया कि अपना प्रयास भारत में एकमात्र ऐसा प्रयास है जो इतना स्पष्ट हो, प्रभावकारी हो और निश्चित समाधान हो। अन्य कोई भी संस्था या संगठन इस दिशा में सक्रिय ही नहीं है और स्पष्ट भी नहीं हैं। गांधी जी और जय प्रकाश जी के नाम पर काम कर रहे संगठन भी स्वराज्य और सुराज्य के स्पष्ट अंतर की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये हो सकता है कि कुछ समय तक हमें अकेले ही चलना पड़े। चूँकि भारत की सभी समस्याओं के समाधान का मार्ग यहीं से शुरू होता है इसलिये धीरे धीरे अन्य संस्थाओं के भी अच्छे लोग इस प्रयास से जुड़ेंगे। वैसे भविष्य यह भी दिखाई देता है कि यह प्रयास समूची दूनियों का मार्गदर्शन करेगा। किन्तु अभी तो हमारा आंदोलन भारत तक ही सीमित है।

(9) लोक स्वराज्य मंच के कार्यकारी अध्यक्ष एक्का जी की सहमति से अभी निम्न राष्ट्रीय पदाधिकारी घोषित हुए हैं:-

(1) उपाध्यक्ष- श्री अमर सिंह जी आर्य, जयपुर।

(2) महासचिव- श्री अनिल पाठक, दिल्ली।

(3) कार्यकारिणी की सदस्य:-

(1) श्री कृष्ण लाल जी रूंगटा, धनबाद।

(2) श्री अशोक त्रिपाठी, वाराणसी।

(3) श्री बहादुर सिंह याद, बदायूँ।

(4) श्री अर्पित अनाम, अम्बाला।

(5) श्री भगवान लाल बंशीवाल, राजसमन्द।

(6) श्री कैलाश साहू जी मधुबनी।

(7) श्री राजनारायण जी गुप्त, बरेली।

(8) श्री सोम प्रताप जी गहलौत, मरेठ।

इसके अतिरिक्त कुछ और नाम शीघ्र ही जोड़े जायेंगे।

(3) लोक स्वराज्य मंच का प्राथमिक सदस्यता शुल्क ग्यारह रूपया आजीवन रखा गया है। ढाई बजे यज्ञ हुआ। उसके बाद व्यक्ति परिवार और समाज विषय पर विस्तृत चर्चा सम्पन्न हुई। अगली बैठक और यज्ञ 25 फरवरी रविवार को साढ़े दस बजे से अपने नये कार्यालय बी- 56, चौथी मंजिल, जैन मंदिर गली, शकरपुर, में होगा। चर्चा का विषय है- “अपराध और अपराध नियंत्रण”। अधिक से अधिक लोग यज्ञ और विचार गोष्ठी में आवे ऐसी अपेक्षा है

## लोक संविधान सभा समिति (प्रस्तावित)

राज्य	नाम	जिला
आन्ध्र प्रदेश	श्री व्ही.व्ही.एस.डी.एस.प्रसाद	हैदराबाद
उड़ीसा	श्री पंचानन सेनापति	भुवनेश्वर
उत्तर प्रदेश	श्री अशोक त्रिपाठी	आगरा
	श्री कृष्ण चंद सहाय	आगरा
	श्री अगम प्रसाद माथुर	आगरा
	श्री राम चंद दुबे	गाजीपुर
	श्री अशोक गादिया	गाजियाबाद
	श्री रामबहादुर राय	गाजियाबाद
	श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव	गोरखपुर
	श्री ओम प्रकाश दुबे	नोएडा
	श्री महावीर सिंह	नोएडा
	श्री घनश्याम गर्ग	नोएडा
	डॉ० मनोज मिश्रा	जौनपुर
	श्री चन्द्रिका चौरसिया	देवरिया
	श्री बहादुर सिंह यादव	बदायूँ
	श्री अशोक त्रिपाठी	वाराणसी
	डॉ० मनोज मिश्रा	जौनपुर
	श्री चन्द्रिका चौरसिया	देवरिया
	श्री बहादुर सिंह यादव	बदायूँ
	श्री अशोक त्रिपाठी	वाराणसी
	डॉ० ए.के.द्विवेदी	वाराणसी
	आचार्य पंकज	वाराणसी
	श्री शरद कुमार साधक	वाराणसी
	श्री राधेश्याम सिंह	वाराणसी
	श्री ओमवीर तोमर	बागपत
	श्री सुकर्म पाल सिंह	बागपत
	श्री योगेश मिश्रा	भदोही
	श्री सेवक शरण	मथुरा

	श्री कृष्ण कुमार खन्ना	मेरठ
	श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल	मेरठ
	श्री उग्रनाथ नागरिक (प्रिय सम्पादक)	लखनऊ
	श्री राजीव जी	लखनऊ
	श्री नरेन्द्र नीरव	सोनभद्र
	श्री देवेन्द्र शास्त्री	सोनभद्र
	श्री ओंकारनाथ दुबे	हमीरपुर
	श्री अरूण कुमार	वाराणसी
	श्री राधेश्याम सिंह(बार0एसो0)	
	डॉ0 रमेश दीक्षित	
उत्तराखण्ड	श्री कासिम हसन सिद्धीकी	देहरादून
	साध्वी कमलेश भारती	हरिद्वार
	श्री प्रमोद कुमार वात्सल्य	ऋषिकेश
	स्वामी मुक्तानन्द जी सरस्वती	हरिद्वार
	महन्त प्रदीप दास	ऋषिकेश
कर्नाटक	श्री एन.एस.शिवानंद	बंगलौर
	श्री विजय कुमार शेषराव	लातूर
	श्री एम.एच पाटिल	धारवाड़
	श्री हीरालाल शर्मा	बंगलौर
केरल	श्री के.जी.बालकृष्ण पिल्लई	त्रिवेन्द्रम
	डॉ0 एन.एन.पणिकर	तिरुअंतपुरम्
गुजरात	श्री जयेन्द्र रमण लाल शाह	अहमदाबाद
	श्री धर्म बन्धु	राजकोट
छत्तीसगढ़	श्री लोकेश कावड़िया	रायपुर
	श्री प्रभु नारायण त्रिपाठी (पूर्व गृहमंत्री)	सरगुजा
	श्री महेन्द्रा मुकीम	रायपुर
जम्मू और	डॉ0 योगेन्द्र शास्त्री	जम्मू
कश्मीर		
झारखण्ड	श्री कृष्ण लाल रूंगटा	धनबाद
	श्री जय किशन	धनबाद

तामिलनाडु

श्री अब्दुल भाई

मदुरई

श्री गुलाब चन्द्र कोटडिया

चेन्नई

दिल्ली

श्री अवधेश कुमार

शंकरपुर

श्री अनिल कुमार उपाध्याय

शालीमार बाग

श्री आर्य भूषण भारद्वाज

भजनपुरा

श्री ए.के.अरुण

पश्चिम बिहार

श्री ओंकार मित्तल

सुखदेव विहार

श्री गोविन्दाचार्य जी

न्यू राजेन्द्र नगर

श्री.टी.एन.जुत्सी

पहाड़गंज

श्रीमती निर्मला शर्मा

राजौरी गार्डन

डॉ० प्रमोद कुमार दुबे

N.C.E.R.T